



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 जून, 2004/31 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 2004

No. EDN-A-Kha (1) 3/2003-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotions of the following Lecturers (Colleges) to the post of Principal (Colleges) in the pay scale of Rs. 12000—18300/- per month with immediate effect, on regular basis, in public interest. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the postings of these newly promoted candidates as Principals in the Colleges shown against their names :—

Sl. No	Name & present place of postings	Place of posting as principals	Remarks
1	2	3	4
1.	Sh. S. C. Bhatia, Lecturer (Phy. Edu.) GC Arki.	GC Sujampur	Against Vacancy
2.	Smt. Sarita Gupta, Lecturer (Eco.) GC Palampur (H. P.).	GC Jogindernagar (Mandi).	-do-

1	2	3	4
3.	Smt. Raksha Kapoor, Lecturer (Eco.) GC Mandi.	GC Mandi	Vice Sh. K. K. Vaidya, who is U/T to Indora.
4.	Sh. R. S. Kapoor, Lecturer (English) GC Kullu.	GC Bhoranj (HMR)	Against Vacancy
5.	Smt. Rita Mahajan, Lecturer (Botany) GC Dharamshala.	GC Nurpur	-do-
6.	Sh. V. V. S. Dogra, Lecturer (Physics) GS Shimla.	Dte of Edu. H. P. Shimla-1, as OSD.	Against vacancy
7.	Shri V. D. Sharma, Lecturer (Math) GC Dehri (KGR)	GC Chowari (CBA)	-do-
8.	Smt. Shashi Sharma, Lecturer (Music-I) RKMV Shimla.	GC Dehri (Kangra)	-do-
9.	Sh. S. P. Sharma, Lecturer (Zoology) GC Theog.	GC Bilaspur	-do-
10.	Sh. P. S. Thakur, Lecturer (Zoology) GC Solan.	GC Karsog	-do-
11.	Sh. M. R. Sharma, Lecturer (Pol. Science) GC D/Shala.	GC Dhaliara (Kangra)	-do-
12.	Smt. Neema Jaswal, Lecturer (Eng.) RKMV Shimla.	GC Nalagarh	-do-
13.	Sh. H. S. Negi, Lecturer (Math) GC Solan.	GC Solan	-do-
14.	Smt. Paramjeet Kaur, Lecturer (Botany) RKMV Shimla.	GC Saraswatinagar (Shimla).	-do-
15.	Smt. Bhagwati Bali, Lecturer (Botany) GC Seema.	GC Arki (Solan)	-do-

1. All the above Principals will be on probation for a period of Two years or till retirement, whichever is earlier.

2. All the above promoted Principals are directed to report for duty at the place of their new postings immediately and send their joining reports to this department through Director of Education, H. P. within a fortnight positively. The above promotions shall be effective only from the date of Joining at the place of their new postings.

3. No extension to join shall be allowed in any case.

By order,

Sd/-  
Pr. Secretary.

# FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 2004

**No. FFE-B-A (4) 7/2003.**—In continuation of this department's notification No. FFE-B-A (4) 1/2001-Loose, dated 31-10-2003 the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Article 23 (i) of the Memorandum and Article of Association of the H. P. State Forest Corporation Ltd., is pleased to appoint Shri Virbhadra Singh, Hon'ble Chief Minister, as Director of the Board of Directors of the H. P. State Forest Corporation Ltd. in place of Shri Chander Kumar the then Hon'ble Forest Minister H. P. with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to appoint Shri Virbhadra Singh, Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh as Chairman of H. P. State Forest Corporation Ltd. in exercise of the powers vested in him under Article 24 of the Memorandum and Article of Association of the said Corporation. These order are hereby issued in pursuance to directions contained in letter No. GAD-C (A) 4-1/2003, dated 27-3-2003.

By order,

J. P. NEGI,  
Principal Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-9, 19 जून, 2004

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 190/2003.—यह कि उपायुक्त सिमौर द्वारा आपको प्रधान, ग्राम पंचायत करगानू, विकास खण्ड राजगढ़, के पद से सरकारी धन राजि के दुरुपयोग व अनियमितताओं में संलग्न होने के आरोप में पत्र संख्या-पी० सी० एन०-एम० एम० आर० (9) 22/97, दिनांक 9-4-2003 द्वारा निलम्बित किया गया था।

यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उप-निदेशक (पंचायत) को इस कार्यालय के आदेश संख्या-पी० सी० एच०-एच० ए०- (5) 190/2003 दिनांक, 8-7-2003 को सौंपी गई थी।

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाये गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त पाया गया कि :

आरोप संख्या-1. ग्राम पंचायत करगानू खुरली निर्माण, जो कि जगाह में किया जाना था. को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्वेच्छा से केदावाली में करवाया गया। जिस हेतु मु० 4363 रु० की राशि व्यय दर्शाई गई है, जबकि मुल्यांकन रिपोर्ट में मु० 2575/- दर्शाई गई है। अतः आप मु० 1788/- रु० के दुरुपयोग के दोषी पाये गये हैं।

आरोप संख्या-2. आप द्वारा निर्माण खुरली, ग्राम वोहल/निर्माण खुरली, ग्राम हियोण/निर्माण खुरली, ग्राम पलाशाला/निर्माण खुरली, ग्राम पलाशाला/निर्माण खुरली, चबुतरा/निर्माण खच्चर रास्ता इन्धन से हिनुण

तक के कार्यों में मुल्यांकन से अधिक व्यय (क्रमशः मु0 948/-, 2185/-, 2270/-, 2007/-, व मु0 23,210/- रु0) करने के दोषी पाये गये हैं।

आरोप संख्या-7. आप मु0 13,000/- रु0 की राशि प्राथमिक पाठशाला धनेच के निर्माण में व्यय के लिये दोषी पाये गये हैं, जबकि यह कार्य पूर्व प्रधान द्वारा पूर्ण किया गया था। उक्त राशि प्राथमिक पाठशाला धुमन के लिए स्वीकृत की गई थी जिसे आप स्वेच्छा से प्राथमिक पाठशाला धनेच के निर्माण में बकाया राशि की अदायगी अनाधिकृत रूप से व्यय करने के दोषी पाये गये हैं।

आरोप संख्या-8 वर्षा शालिका ग्राम धनेच के निर्माण में मु0 400/- रु0 मुल्यांकन राशि मु0 24,600/- से अधिक मु0 25,000/- व्यय करने के दोषी पाये गये हैं।

आरोप संख्या-9 निर्माण आंगनवाड़ी भवन नेरी में भी मु0 520/- रु0 मुल्यांकन राशि मु0 79,480/- से अधिक मु0 80,000/- रु0 व्यय करने के भी दोषी पाये गये हैं।

आरोप संख्या 1 से 9 पर जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट का सरकार द्वारा विचार करने के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि आप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (बी) के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से दोषी हैं।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप द्वारा बरती गई उपरोक्त वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए क्यों न आपको प्रधान पद से निष्कासित किया जाये।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर दे। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (2) के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उप निर्देशक (पंचायत) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न भेजी जा रही है।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
सचिव।